

MODEL ANSWER

Q. Discuss the historical, economic, and geopolitical dimensions of India-China relations. Highlight the key challenges in the bilateral relationship and suggest measures India can adopt to navigate these challenges effectively.

India and China, the two most populous nations and major global economies, share a complex relationship shaped by historical interactions, economic ties, and geopolitical competition. Their relationship has been marked by cultural exchanges, border disputes, economic interdependence, and strategic rivalries. Given the shared 3,488 km border, managing bilateral relations is crucial for regional stability and global economic dynamics.

Historical Dimensions

- Ancient Civilizational Ties: India and China shared strong cultural and trade connections via the Silk Road. Buddhism, carried by monks like Fa Xian and Xuan Zang, played a vital role in fostering intellectual exchange.
- **Border Conflict Legacy**:
 - 1962 War: The war over Aksai Chin and Arunachal Pradesh significantly shaped mutual perceptions, with China consolidating control over Aksai Chin.
 - **Border Clashes**: Since 1962, tensions have flared up, including the Sumdorong Chu incident (1986), Doklam standoff (2017), and the Galwan Valley clash (2020), which was the first deadly conflict in decades.
- LAC Ambiguity:
 - India considers the Line of Actual Control (LAC) to be 3,488 km long, while China recognizes only around 2,000 km.
 - It is divided into three sectors:
 - 1. Eastern sector (Arunachal Pradesh & Sikkim) McMahon Line (1,140 km).
 - 2. **Middle sector** (Uttarakhand & Himachal Pradesh).
 - 3. **Western sector** (Ladakh).
 - o Unlike the Line of Control (LoC) with Pakistan, which is mapped and agreed upon, the LAC remains an evolving concept, leading to frequent tensions.

Economic Dimensions

- Bilateral Trade: China is India's second-largest trading partner, with bilateral trade reaching \$136 billion in 2023, though India faces a trade deficit exceeding \$100 billion.
- **Dependency on Chinese Imports**: India is highly import dependent in sectors such as Pharmaceuticals (70% of API imports from China), Electronics, Telecom and Solar energy components.

Geopolitical Dimensions

- Major Friction Points along the LAC: The India-China border dispute remains a key point of contention, with several major friction points along the Line of Actual Control (LAC). In northern Ladakh, the Depsang Plains witness frequent Chinese incursions, while Demchok remains a site of ongoing disputes over border demarcation. The Pangong Lake region has been a flashpoint where China attempted to alter the status quo, leading to military confrontations. Similarly, Gogra and Hot Springs have experienced recurring standoffs between Indian and Chinese troops. In the eastern sector, China claims Arunachal Pradesh as "South Tibet", challenging India's sovereignty and escalating diplomatic
- Chinese Strategic Approaches: China employs multiple strategic approaches to assert its dominance.
 - The Salami Slicing Strategy involves gradual, incremental encroachments to alter territorial claims without triggering full-scale conflict.



- The Five Fingers of Tibet strategy seeks to expand Chinese influence over Nepal, Bhutan, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Ladakh, considering them extensions of Tibet.
- Additionally, through its String of Pearls strategy, China is expanding its naval presence in the Indian Ocean by establishing ports in strategic locations like Gwadar (Pakistan) and Hambantota (Sri Lanka), thereby increasing its influence in India's maritime neighborhood.
- Water Security Concerns: China's control over the Brahmaputra River and its dam projects raise concerns about India's water access.
- **Cybersecurity Threats**: Rising cyber-attacks attributed to China highlight vulnerabilities in India's digital infrastructure.

Resolving the India-China border dispute is challenging due to deep-seated mistrust, particularly after the Galwan Valley clash (2020), which strained diplomatic efforts. The ambiguous nature of the LAC further complicates resolution, as it remains neither formally demarcated nor mutually recognized. Although disengagement agreements exist, the implementation process is slow, requiring careful negotiation. Meanwhile, China's rapid military buildup along the LAC, coupled with its assertive posturing, signals long-term strategic competition, making de-escalation difficult.

Beyond the border, geopolitical tensions shape bilateral relations. India's participation in QUAD (India, U.S., Japan, Australia) and I2U2 (India-Israel-UAE-USA) is seen as a counterbalance to China, while Beijing expands its influence through the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and Belt and Road Initiative (BRI). To navigate these challenges, India must strengthen diplomatic channels, invest in border infrastructure (Bharatmala, Vibrant Villages Programme), and reduce economic dependence by boosting domestic manufacturing. Military modernization, alongside strategic alliances with QUAD, ASEAN, and Indian Ocean Region (IOR) nations, will be crucial in countering China's growing regional dominance.

An Institute For Civil Services



प्रश्न: भारत-चीन संबंधों के ऐतिहासिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयामों पर चर्चा करें। द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और सुझाव दें कि भारत इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या उपाय अपना सकता है।

भारत और चीन, जो कि दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश एवं प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, अपने ऐतिहासिक परस्पर क्रियाओं, आर्थिक संबंधों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा जिटल रिश्तों को साझा करते हैं। इनके संबंधों की पहचान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सीमा विवाद, आर्थिक परस्पर निर्भरता और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता की जाती है। दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी साझा सीमा होने के कारण, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता के लिए द्विपक्षीय संबंधों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक आयाम

- प्राचीन सभ्यतागत संबंध: भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से सिल्क रोड के माध्यम से गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। फ़ाहियान और झांग जुआन जैसे बौद्ध भिक्षुओं के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसने बौद्धिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती दी।
- सीमा संघर्ष का इतिहास:
 - 1962 का युद्धः अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर हुआ युद्ध दोनों देशों के रिश्तों पर एक स्थायी छाप छोड गया है। इस संघर्ष ने चीन को अक्साई चिन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में मदद की।
 - सीमा संघर्ष: 1962 के युद्ध के बाद से सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा है, और प्रमुख घटनाएँ सामने आईं, जैसे सुमदोरोंग चू घटना (1986), डोकलाम संघर्ष (2017), और गलवान घाटी संघर्ष (2020)।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा की अस्पष्टताः
 - भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबिक चीन इसे केवल
 2,000 किलोमीटर के आसपास मानता है।
 - LAC को तीन मुख्य सेक्टरों में बांटा गया है:
 - पूर्वी सेक्टर (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम) मैकमोहन रेखा (1,140 किलोमीटर)।
 - मध्य सेक्टर (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)।
 - पश्चिमी सेक्टर (लद्दाख)।
 - पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थिति के विपरीत, LAC अभी भी एक अस्पष्ट अवधारणा है,
 जिससे सीमा पर अक्सर तनाव उत्पन्न होता है।

आर्थिक आयाम

- द्विपक्षीय व्यापार: चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 136 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, हालाँकि भारत को 100 बिलियन डॉलर से अधिक के व्यापार घाटे का सामना भी करना पड़ रहा है।
- चीनी आयात पर निर्भरता: भारत फार्मास्यूटिकल्स (चीन से API आयात का 70%), इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सौर ऊर्जा घटकों जैसे क्षेत्रों में आयात पर अत्यधिक निर्भर है।

भू-राजनीतिक आयाम

- LAC पर प्रमुख घर्षण बिंदु: भारत-चीन सीमा विवाद का एक प्रमुख बिंदु वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर विवाद हैं। उत्तरी लद्दाख के देपसांग मैदानों में अक्सर चीनी घुसपैठ देखी जाती है, जबिक देमचोक सीमा विवाद का केंद्र बना हुआ है। पैंगोंग झील क्षेत्र एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ चीन ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसके कारण सैन्य भी टकराव हुए है। इसी प्रकार, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई बार टकराव हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र में, चीन अरुणाचल प्रदेश को "दक्षिण तिब्बत" के रूप में देखता है, जिसके कारण भारत की संप्रभृता को चुनौती मिलती है और कुटनीतिक तनाव बढाता है।
- **चीनी रणनीतिक दृष्टिकोण:** चीन अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए कई रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाता है।
 - सलामी स्लाइसिंग रणनीति में पूर्ण पैमाने पर संघर्ष को ट्रिगर किए बिना क्षेत्रीय दावों को बदलने के लिए क्रमिक, वृद्धिशील अतिक्रमण शामिल हैं।



- चीन अपनी फाइव फिंगर रणनीतिक से नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को तिब्बत का विस्तार मानते हुए, उन पर चीनी प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, ।
- इसके अतिरिक्त, अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से, चीन ग्वादर (पाकिस्तान) और हंबनटोटा (श्रीलंका) जैसे रणनीतिक स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापना करके हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिससे भारत के समुद्री पड़ोस में उसका प्रभाव बढ़ रहा है।
- जल सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी बांध परियोजनाओं पर चीन का नियंत्रण भारत के लिए चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे:** चीन द्वारा किए जा रहे बढ़ते साइबर हमले भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद का समाधान अत्यधिक अविश्वास के कारण चुनौतीपूर्ण रहा है, विशेष रूप से गलवान घाटी संघर्ष (2020) के बाद, जिसने कूटनीतिक प्रयासों को प्रभावित किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की अस्पष्ट प्रकृति समाधान को और भी जटिल बनाती है, क्योंकि यह न तो औपचारिक रूप से सीमांकित है और न ही पारस्परिक रूप से स्वीकृत है। हालांकि विघटन संबंधी समझौते मौजूद हैं, परंतु कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रिया धीमी है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक एक वार्ता की आवश्यकता है। इस बीच, LAC पर चीन का तेज़ी से सैन्य अतिक्रमण और उसका मुखर रुख दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिससे तनाव को कम करना और भी कठिन हो जाता है।

सीमा विवाद से परे, भू-राजनीतिक तनाव द्विपक्षीय संबंधों को आकार देते हैं। भारत की क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और 12U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-यूएसए) जैसी पहल में भागीदारी को चीन के प्रति संतुलन साधने के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि चीन बीजिंग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को कूटनीतिक चैनलों को मजबूत करने की आवश्यकता है, सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे (जैसे भारतमाला और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) में निवेश करना चाहिए और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहिए। साथ ही, क्वाड, आसियान और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) देशों के साथ रणनीतिक गठबंधन और सैन्य आधुनिकीकरण चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभुत्व का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

An Institute For Civil Services